¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ 2014-15
(10 VÉãÉÉ<, 2014)

¤ÉEàÉ oÉ.	{É®É oÉ.	¤ÉVÉ] PÉÉKÉhÉÉ	BÉEÉ¤aÉÉx´ÉaÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÉoIÉÉiÉ
1	8	´aÉaÉ |ÉªÉVÉ +ÉÉaÉÉMÉ सरकार व्यय प्रबंध आयोग का गठन करेगी। यह सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। यह आयोग इसी वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मैं, खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडियों सहित सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा करने और उपेक्षित, गरीबों और अनुसूचित जातियों/ जनजातियों को पूरी सुरक्षा देते हुए, इसे अधिक लक्ष्यपरक बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः व्यय विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग]	व्यय प्रबंध आयोग 4 सितम्बर, 2014 को गठित किया गया। इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 17.1.2015 को प्रस्तुत कर दी है। एलपीजीः एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए संशोधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल देश के 54 जिलों में 15.11.2014 को शुरू की गई थी। यह 1.1.2015 से देश के शेष जिलों में शुरू की गई है। नई यूरिया नीति बनाने का कार्य चल रहा है। BÉEÉ®´ÉÉ< +ÉÉÉ¶ÉBÉE °ô{É ºÉ {ÉhÉ
2	9	´ÉºiÉ A´É ºÉ´ÉÉ BÉE® (VÉÉAºÉ]É) क्या वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए अब बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए। हमने विगत कई वर्षों में इस मुद्दे पर चर्चा की है। कुछ राज्य अपने कराधान क्षेत्राधिकार के समर्पण से डरे हुए हैं और अन्य पर्याप्त क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। मैंने इस विषय पर राज्यों से अलग-अलग और सामूहिक रूप से चर्चा की है। मुझे आशा है कि इस वर्ष कोई समाधान ढूंढ लेंगे और विधायी योजना अनुमोदित करेंगे। इससे वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सकेगा। यह केंद्र और राज्य दोनों के कर प्रशासन को सुप्रवाही बनाने, व्यवसाय में परेशानी से बचाने और उच्च राजस्व संग्रहण के परिणाम देगा। मैं, सभी राज्यों को आश्वासन देता हूँ कि सरकार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव 17.12.2014 को अनुमोदित किया जिससे कि देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने में आसानी हो। यह विधेयक लोकसभा में 19.12.2014 को पुरःस्थापित किया गया। BÉEÉ®´ÉÉ< |ÉMÉÉiÉ {É®
3	10	BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ सरकार के पूर्वव्यापी कराधान का उत्तरदायित्व लेने के शासकीय अधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तथापि, इस शक्ति का प्रयोग अर्थव्यवस्था और समग्र निवेश माहौल पर ऐसे प्रत्येक उपाय के प्रभाव को ध्यान में रखकर अत्यंत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए। (i) यह सरकार सामान्यतया पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं करेगी जो नई देनदारी सृजित करे। माननीय सदस्यों को पता है कि वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए आयकर अधिनियम,	

क्रम संख्या	तारांकित प्रश्न संख्या	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर की संक्षिप्त जानकारी
			ÉÉÉMÉãÉ{É® àÉ ´É°jÉ =tÉÉMÉ àÉMÉÉ BÉãÉ°]® : एनआईएफटी, पटना के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि उन्हें क्लस्टर मैनेजमेंट एण्ड टेकनिकल एजेंसी (सीएमटीए) के रूप में नियोजित किया जा सके। क्लस्टर का बेसलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है। सीएमटीए द्वारा 15.1.2015 तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। iÉÉàÉãÉxÉÉb àÉ ´É°jÉ =tÉÉMÉ àÉMÉÉ BÉãÉ°]® : सीएमटीए के रूप में नियोजित करने के लिए मैसर्स तमिलनाडु हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदनार्थ परियोजना अनुमोदन और मानीटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। °É®iÉ (MÉVÉ®ÉiÉ) àÉ ´É°jÉ =tÉÉMÉ àÉMÉÉ BÉãÉ°]®: क्लस्टर मैनेजमेंट एण्ड टेकनिकल एजेंसी (सीएमटीए) के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है। ´É°jÉ =tÉÉMÉ àÉMÉÉ BÉãÉ°]®, à¤°É® : कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (केएसटीआईडीसी) को सीएमटीए बनाने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। BÉÉÉªÉ |ÉMÉÉiÉ {É®
94	108 मैं, दिल्ली में पीपीपी प्रणाली में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण, बहाली और प्रलेखन के लिए एक हस्तकला अकादमी स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि रखता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः वस्त्र मंत्रालय]		व्यय वित्त समिति ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है। BÉÉÉªÉ |ÉMÉÉiÉ {É®
95	109 मैं, जम्मू-कश्मीर के अन्य हस्त शिल्पों के विकास के लिए पशमिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपए की राशि रख रहा हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः वस्त्र मंत्रालय]		पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) 8.10.2014 को शुरू किया गया है। माननीय वस्त्र उद्योग राज्य मंत्री द्वारा दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है। जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प परियोजनाओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण/ नैदानिक अध्ययन करने हेतु और एसपीवी के निर्माण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करने के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय अभिकल्प और उत्पाद विकास केन्द्र को नियुक्त किया जाएगा। 25.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। BÉÉÉ®´ÉÉ< +ÉÉÉ¶ÉBÉÉ °ô{É °É {ÉhÉ

क्रम सं.	उत्तर सं.	प्रश्न	उत्तर

96 110 **श्री** पीपीपी बाजार

भारत विश्व में सबसे बड़ा पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है जहां विकास के विभिन्न चरणों में 900 से अधिक परियोजनाएं हैं। पीपीपी ने हवाईअड्डों, पत्तनों और राजमार्गों जैसी कुछेक विशिष्ट अवसंरचना प्रदान की हैं जो वैश्विक रूप से विकास के लिए मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। किंतु हमने पीपीपी प्रेमवर्क की खामियों कठोर संविदात्मक व्यवस्थाओं, अधिक सूक्ष्म और संविदा की परिष्कृत मॉडलों को विकसित करने की जरूरत और कठिन परियोजनाओं के दबाव को कम करने के लिए त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया विकसित करने की खामियों को भी देखा है। सरकारी निजी भागीदारी जिन्हें 3 पी इंडिया कहा जाता है को मुख्यधारा में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की संग्रहराशि से एक संस्था की स्थापना की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

3पी इंडिया इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के संबंध में मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार है। यह मंत्रिमंडल टिप्पणी फरवरी, 2015 में मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी जाएगी।

97 111 **श्री** भारतीय नियंत्रित टन भार

भारतीय नियंत्रित टन भार की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी जिसे कि भारतीय समुद्री यात्रियों के रोजगार में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। व्यापार बढ़ाने के लिए पत्तनों का विकास भी महत्वपूर्ण है। पत्तन संयोजकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस वर्ष सोलह नई पत्तन परियोजनाओं की संविदा दिए जाने का प्रस्ताव है। चरण I के लिए तूतीकोरिन में बाहरी बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए 11,635 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएंगें। कांडला और जेएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की भी घोषणा की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पोत परिवहन मंत्रालय; वाणिज्य मंत्रालय]

(?) श्री नितिगत निर्णय ले लिया गया है और महानिदेशक (पोत परिवहन) द्वारा 23.7.2014 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(??) श्री : 11 बंदरगाह परियोजनाओं के निर्माण कार्य की संविदा दे दी गई है।

(???) श्री : यह परियोजना 5 नवंबर, 2014 को 5686 करोड़ रुपए के जेआईसीए सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के लिए जापान सरकार को प्रस्तुत की गई है।

(iv) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में सेज का शुभारंभ 16.8.2014 को किया गया है।

कांडला पत्तन न्यास के लिए वाणिज्य मंत्रालय का सिद्धांततः अनुमोदन जुलाई, 2015 तक बढ़ा दिया गया है।

(i) ''नई पोत निर्माण विकास योजना'' संबंधी मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी अंतर-मंत्रालययी परामर्शों के लिए परिचालित की गयी है।

98 112 **श्री** अंतर देशीय जलमार्ग

अंतर देशीय जलमार्ग का विकास करने से, सामान की ढुलाई क्षमता व्यापक रूप से सुधारी जा सकती है। 1620 कि.मी. की दूरी कवर करने के लिए

परियोजना मानीटरिंग एकक की स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सितंबर, 2014 के दूसरे सप्ताह में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के लिए हित

क्रम संख्या	तारांकित संख्या	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर की तारीख

इलाहाबाद और हल्दिया के बीच ''जल मार्ग विकास'' (राष्ट्रीय जल मार्ग-I) नामक गंगा नदी परियोजना विकसित की जाएगी। इससे कम से कम 1500 टन भार वाले जलयानों का वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। यह परियोजना 4200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से छह वर्ष में पूरी होगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पोत परिवहन मंत्रालय]

अभिव्यक्तियां जारी कर दी गई हैं। हित अभिव्यक्तियों के बारे में जवाब मिल चुका है। आईडब्ल्यूएआई ने डीपीआर तैयार करने तथा ईआईए/ईएमपी अध्ययन के लिए परामर्शदाताओं की सूची तैयार की है।

बीईईआईएम/ईएमईआई/ईएस

99 113 एएच ईएसएसईकेएच

हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के बावजूद, हवाई यात्रा अभी भी अधिकांश इच्छुक भारतीयों की पहुंच से बाहर है। टीयर-I तथा टीयर-II में नए विमानपत्तनों के विकास की स्कीम शुरू की जाएगी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या सरकारी निजी भागीदारीवाली परियोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः नागर विमानन मंत्रालय]

यह निर्णय लिया गया है कि आबादी, दूरी का मापदंड और पर्यटन और उद्योग की संभावना को ध्यान में रखते हुए देशभर के टीयर-II और टीयर-III शहरों में 'नो फ्रिल्स' हवाई-अड्डों का विकास किया जाए। अब तक, पचास स्थानों की पहचान की गई है।

2014-15 में छोटे हवाई-अड्डों के निर्माण हेतु कार्य शुरू करने हेतु पांच हवाई-अड्डे नामतः कर्नाटक में हुबली और बेलगाम; राजस्थान में किशनगढ़; ओडिशा में झारसूगुडा और अरूणाचल प्रदेश में तेजू की पहचान की गई है और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष 45 स्थानों की समीक्षा, न्यूनतम 10 लाख की आबादी, पर्यटन संभावना, विमान पत्तन प्रचालनों की आर्थिक क्षमता, विगत में उड़ानों के ब्यौरे इत्यादि जैसे व्यापक मापदंडों के आधार पर की जाएगी।

बीईईआईएम/ईएमईआई/ईएस

100 114 ओएचबीईई एफजेई

सड़क क्षेत्र देश के संचार में अत्यंत महत्वपूर्ण धमनी का कार्य करता है। इस क्षेत्र को 1998-2004 में एन.डी.ए-I के काल में तैयार किया गया था। स्वीकृतियों से रूकावटों को हटाने के साथ-साथ, इस क्षेत्र में भारी निवेश किए जाने की पुनः आवश्यकता है। मैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सड़कों में 37,880 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें 3000 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए होंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 8500 कि.मी. लंबे राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]

दिसम्बर, 2014 तक, 2475 कि.मी. लम्बे राजमार्ग का निर्माण किया गया है।

बीईईआईएम/ईएमईआई/ईएस

101 116 ईईटीईई

अधिक स्वच्छ और प्रभावी ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए, मैं ''अल्ट्रा माडर्न सुपर क्रिटीकल कोल आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी'' नामक नई परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः भारी उद्योग विभाग]

व्यय वित्त समिति ने थर्मल पावर प्लांट के लिए एडवांसड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मिशन मोड में विकास की अनुसंधान व विकास परियोजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

आर एंड डी परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना कार्य शुरू करने के लिए भेल से अनुरोध किया गया है। आर्थिक कार्य संबंधी

क्रम संख्या	तारांकित/अतारांकित	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर देने की तारीख

मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के बाद, 100.00 करोड़ रुपए की राशि भेल को जारी कर दी जाएगी।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ टिप्पण का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है।

कोयला मंत्रालय

102 117 कोयला क्षेत्र

घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक बन्दोबस्त किए जा रहे हैं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कठोर तंत्र है, जिसमें क्रश्ड कोल की आपूर्ति और वाशरीज की स्थापना भी शामिल है। कोयला क्षेत्र में विद्यमान गतिरोध दूर कर लिया जाएगा और उन विद्युत संयंत्रों को कोयला की प्रर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएगी जो पहले से काम शुरू कर चुके हैं या मार्च, 2015 तक काम शुरू कर देंगे ताकि निवेश निष्क्रिय न रहे। कोयला लिंकेज के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है जिससे कोयला की इष्टतम ढुलाई होगी और विद्युत की लागत कम आएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः कोयला मंत्रालय]

वर्ष 2019-20 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन कार्य योजना के अनुसार विभिन्न परियोजनाओ के समय पर क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई, कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पश्चात की जाएगी।

कोयला पूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, थर्ड पार्टी सैंपलिंग की कार्य पद्धति 01.10.2013 से लागू की गई थी। एनटीपीसी जैसी पावर युटिलिटिज और अन्य, टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से थर्ड पार्टी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया में लगी हैं।

कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया गया है।

कोयला ब्लाकों की ई-नीलामी शुरू हो गई है। पहले चालू किए गए अथवा मार्च, 2015 तक चालू होने वाले पावर प्लांट प्रतिस्पर्धी बोली में भाग ले सकते हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

103 118 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए, मैंने 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किया है। एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सौर ऊर्जा चलित कृषि पम्प सेट तथा जल पम्पिंग केंद्र के लिए एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए, मैं 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। नहरों के किनारे 1 मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरण सुसाध्य बनाने के लिए, हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना को इस वित्त वर्ष में त्वरित किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय]

सोलर पार्कों के विकास की योजना और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजना मंत्रिमंडल द्वारा उसकी 10.12.2014 को हुई बैठक में अनुमोदित की गई थी। इस योजना के मार्ग-निर्देश 12.12.2014 को जारी कर दिए गए।

सोलर पम्पों के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना को कृषि मंत्रालय तथा पेयजल आपूर्ति मंत्रालय की योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है ताकि ड्रिप सिंचाई, जल को काम में लेने आदि को सोलर पम्पों की योजना के साथ संयुक्त किया जाए जिससे किसान के लिए पूर्ण समाधान हो।

मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश में ''कैनाल बैंकों और कैनाल टॉप्स" के बारे में एक पायलेट कम डिमोन्ट्रेशन प्रोजेक्ट फॉर डेवेलपमेंट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर, पीवी पावर प्लांट्स को 975 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एवं 228 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से क्रियान्वयन के लिए मंजूरी 05.12.2014 को जारी की है।

क्रम.सं.	उत्तर देने की तारीख	माननीय सदस्य का नाम	प्रश्न का विषय

अंतर-राज्यिक ट्रांसमिशन स्कीमों के टेंडर का कार्य, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जुलाई, 2014 में किया गया है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 10.12.2014 को हुई अपनी बैठक में तमिलनाडु के लिए 637.2 करोड़ रुपए की एनसीईएफ सहायता का प्रस्ताव अनुमोदित किया। तमिलनाडु ने टेंडर प्रक्रिया का कार्य शुरू कर दिया है।

चालू वर्ष के लिए कार्रवाई पूर्ण हो गई।

ऊर्जा मंत्री

104 119 श्री आर. धुरुवनारायणन
मेरी सरकार की मंशा है कि कोयला बेड मिथेन का उत्पादन और दोहन त्वरित गति से किया जाए। ऐसे स्थलों से अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए पुराने या बंद पड़े कुआँ को दोबारा खोलने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की भी तलाश की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय]

कोल बेड मिथेन नीति के संशोधन के अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला विस्तृत टिप्पण तैयार किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित मुद्दों की ओर भी ध्यान दिया जाएगाः
(i) सरकारी और निजी दोनों प्रकार विभिन्न कंपनियों को आबंटित कोल खदान लीज़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन और अन्वेषण और दोहन की अनुमति देना;
(ii) कोल बेड मिथेन के उत्पादन के लिए निवेश के प्रोत्साहन हेतु ठेकेदार को किसी आबंटन प्राथमिकता का अनुसरण किए बिना, कीमत नीलामी पर आधारित गैस को बेचने की अनुमति होगी;
(iii) कार्यों के सूक्षम प्रबंध को समाप्त करने हेतु मौजूदा कोल बेड मिथेन संविदाओं को सरल बनाना; और
(iv) सीबीएम और कोयला/तेल एवं गैस ब्लाकों की अतिव्याप्ति के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कामचलाऊ प्रणाली लागू करना।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

105 120 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग, मिशन मोड में, तेजी से बढ़ाया जाएगा क्योंकि यह स्वच्छ है और इसकी प्रदायगी में सहूलियत होती है।

नगर गैस वितरण निकायों को गेल (इंडिया) लिमिटेड के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए, नीतिगत दिशानिर्देश अगस्त, 2014 में तैयार किए गए। संबंधित नगर गैस वितरण नेटवर्कों द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछले छह महीने के उपभोक्ता आंकड़ों पर आधारित सीएनजी (परिवहन) और घरेलू पीएनजी प्रखण्डों की शतप्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, घरेलू गैस सप्लाई की जाती है। घरेलू गैस की आपूर्ति करके नगर गैस वितरण सेक्टर (सीएनजी और घरेलू पीएनजी) की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए गेल को अनुमति दी गई है। वित्त वर्ष 2014-15 के नौ महीनों में 1.9 लाख पीएनजी परिवारों को जोड़ा जा रहा है। 11 राज्यों में लगभग 27.37 लाख परिवार पीएनजी सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं। देश में 969 फिलिंग स्टेशनों के माध्यम से, नगर गैस वितरण नेटवर्क भी 22 लाख व्हीकल्स को सीएनजी सप्लाई कर रहे हैं। नगर गैस वितरण नेटवर्क 28000 औद्योगिक और वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं की गैस मांग को भी पूरा कर रहा है।

क्रम सं.	उत्तर सं.	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न

उत्तर में निम्नलिखित कथन किया गया:

i. मौजूदा और प्रस्तावित ट्रंक पाइपलाइन के आस-पास वाले शहरों को अभिज्ञात किया गया है।

ii. चूंकि यह स्पष्ट है कि इस सेक्टर के लिए घरेलू गैस उपलब्ध करा दी जाएगी, इसलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को सलाह दी गई है कि वह अपनी नीलामी प्रक्रिया इस ढंग से बनाए जिससे कि मौजूदा पाइपलाइन के आस-पास के शहरों को पहले समाविष्ट किया जा सके।

iii. जो शहर प्रस्तावित पाइपलाइन के आस-पास आएंगे उनके बारे में इस बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह पाइप लाइन के विकास की नीलामी प्रक्रिया के कार्य में तालमेल लाए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान

106 121 इस समय देश में हमारे पास 15,000 कि.मी. गैस पाइप लाइन सिस्टम है। देश भर में गैस ग्रिड पूरा करने के लिए, अतिरिक्त 15,000 कि. मी. पाइपलाइन की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त सरकारी निजी भागीदारी माडलों का उपयोग करते हुए इन पाइप लाइनों का विस्तार किया जाए। इससे घरेलू तथा आयातित गैस का उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो लम्बे समय में ऊर्जा के किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने में फायदेमंद होगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय]

गैस ग्रिड के विकास के लिए निम्नलिखित पाइपलाइनों की पहचान की गई है:

क्रम सं.	पाइपलाइन का नाम	लंबाई (कि.मी.)
1	काकीनाड़ा- हल्दिया	1100
2	काकीनाड़ा- चेन्नइ	600
3	चेन्नई- तूतीकोरिन	670
4	जगदीशपुर- हल्दिया	2050
5	बरौनी- गुवाहाटी	800
6	सूरत-पारादीप	2050
7	मल्लावरम- भीलवाड़ा	1584
8	मेहसाना- भटिंडा	1670
9	भटिंडा- श्रीनगर	740
10	कोच्चि- बैंगलुरू- मंगलुरू	1348
11	स्परलाइन्स (चरण-I)	2500
	कुल	15112

व्यवहार्यता अंतर निधियन से सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर रांची-तलचर-पारादीप पाइपलाइन खंड के क्रियान्वयन के लिए ''प्रायोजन प्राधिकारी'' के रूप में गेल को चिह्नित किया गया है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान

107 122 जी.

पर्यावरणीय सरोकारों का त्याग किए बगैर, उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए खनन सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देना और सतत खनन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना मेरी सरकार की मंशा है। लौह अयस्क के खनन सहित खनन सेक्टर में बाधाओं को शीघ्रता से दूर कर लिया जाएगा। इसे सुसाध्य बनाने के लिए, यदि आवश्यक हुआ एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन किए जाएंगे।

[नोडल मंत्रालय/विभागः खान मंत्रालय]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया है तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 का प्रख्यापन 12.01.2015 को किया गया है।

श्री गोपीनाथ मुंडे

क्रॅएॅ ओॅ.	{ॅ®ॅ ओॅ.	¤ॅVॅ] PॅॅKॅhॅॅ	Bॅॅॅaॅॅxॅ´ॅaॅxॅ Bॅॅॅ |ॅॅॅoIॅॅiॅ

108 123 ®ॅaॅã]ॅ n® àॅ oॅ¶ॅॅvॅxॅ

खनिजों पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिए अनेक राज्य सरकारों से अनुरोध किए गए हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि रायल्टी में संशोधन तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है। पिछली बार अगस्त, 2009 में संशोधन किया गया था। अतः राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक राजस्व सुनिश्चित करने हेतु और एक संशोधन किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः खान मंत्रालय]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची संशोधित की गई। अधिसूचना 01.09.2014 को जारी की गई।

Bॅॅॅ®´ॅॅ< {ॅhॅ

109 124 **VI.** ॅ´ॅkॅॅaॅ oॅBॅ]®
{ॅVॅॅ ¤ॅॅVॅॅ®

वित्तीय सेक्टर विकास इंजन का केंद्र बिन्दु है। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण विदेशी बचतों को भारत लाने में सहायता करता है। अपितु वित्तीय सेक्टर को वैश्विक अर्थव्यवस्था की लहर से असुरक्षित भी बना देता है। हमने इसे बहुतायत में विगत हाल में देखा है। कानूनी विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और आधुनिक बनाना अनिवार्य है। वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, भारतीय वित्तीय संहिता का अधिनियमन जो बेहतर अभिशासन और जवाबदेही के लिए आवश्यक समझा जाता है। मेरा प्रयास होगा कि इस पर शीघ्रता से सभी हितधारकों के साथ परामर्श की चालू प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बढ़ती जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा होना भी अनिवार्य है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन परामर्श करके ऐसा मौद्रिक नीति ढांचा क्रियान्वित करेगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

वित्तीय सेक्टर अपील अधिकरण के लिए मौजूदा प्रतिभूति अपील अधिकरण के उन्नयन की रूपरेखा निर्धारित करने तथा समाधान निगम, लोक ऋण प्रबंध एजेंसी एवं वित्तीय डाटा प्रबंध केंद्र जैसी नई एजेंसियों की स्थापना करने के लिए कार्यबलों का गठन 30 सितम्बर, 2014 को किया गया। इन बलों के अपनी रिपोर्टें 30 सितम्बर, 2015 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

सभी स्टेकहोल्डरों से प्राप्त अभिमतों के आधार पर भारतीय वित्तीय संहिता के प्रारूप को ठीक किया जा रहा है।

भारतीय वित्तीय संहिता के विधायन में सम्मिलित विभिन्न उपायों के लिए समय-सीमाएं निश्चित की गई हैं।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच किए जाने वाले मौद्रिक नीति संबंधी करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Bॅॅॅaॅ |ॅMॅॅiॅ {ॅ®

110 125 यद्यपि उपर्युक्त उपायों का प्रभाव मध्यावधि में महसूस किया जाएगा, इसी उद्देश्य के लिए, मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँः

i) वित्तीय सेक्टर के विनियामकों को जीवंत, व्यापक और नकदी कारपोरेट बांड बाजार के लिए तुरन्त कदम उठाने और अनावश्यक अड़चनों को दूर करके मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को गहन बनाने की सलाह देना।

ii) सभी सेक्टरों के लिए विदेश में भारतीय कारपोरेट द्वारा जारी सभी बांडों में 5 प्रतिशत विदहोल्डिंग

भारतीय वित्तीय सेक्टर संबंधी विशेषज्ञ स्थायी परिषद की उप-समिति से रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है जिसमें, अनावश्यक प्रतिबंध हटाकर, करेंसी व्युत्पन्न बाजार को गहन बनाने संबंधी नीतिगत प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इस मामले पर एफएसडीसी द्वारा भी विचार-विमर्श किया गया था तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जा रही है।

इस उप समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए उप-स्थायी समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी।

इन उद्घोषणाओं को प्रभावी करने के लिए, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 194ठग को

क्रÉÉàÉ oÉ.	{É®É oÉ.	¤ÉVÉ] PÉÉKÉhÉÉ	BÉÉÉªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉÉÉ |ÉÉÉºIÉÉiÉ
		टैक्स की उदारीकृत सुविधा देना और स्कीम की वैधता 30-06-2017 तक बढ़ाना।	संशोधित किया गया है।
		iii) सभी अनुमेय प्रतिभूतियों के बारे में निक्षेपागार प्राप्तियां जारी करने की अनुमति देने के लिए एडीआर/जीडीआर के दायरे को उदार बनाना।	संशोधित एडीआर/जीडीआर योजना स्वीकृत कर ली गई है तथा उसे, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सेबी द्वारा उपयुक्त संशोधन किए जाते ही, शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।
		iv) भारतीय ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय निपटारा करने की अनुमति देना।	भारतीय ऋण प्रतिभूतियों की यूरोशोध्यता को अंतिम रूप देने और क्रियान्वित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी के साथ बातचीत चल रही है।
		v) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का पूरी तरह पुनर्जीवित करना और कहीं अधिक उदार और महत्वाकांक्षी भारत निक्षेपागार प्राप्ति शुरू करना।	भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति के बारे में साहू कमेटी (फेज-।। पार्ट-।) रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा उसे, जन विचारों एवं अभिमतों के अनुरोध के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
		vi) चिरकालिक समस्या का समाधान करने के लिए जिन निधियों के प्रंबधक भारत में स्थित है उन विदेशी निधियों की आय पर कर उपाय स्पष्ट करना। ब्यौरा भाग II में प्रस्तुत किया जाएगा।	इस उद्घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 2(14) को संशोधित किया गया है। BÉÉÉ®´ÉÉ< +ÉÉÉ¶ÉBÉÉ °ô{É oÉ {ÉhÉ
		[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग; राजस्व विभाग]	
111	126	भारतीय पूंजी बाजार, विकासशील भारत के लिए जोखिम पूंजी के स्रोत रहे हैं। मैं, इन बाजारों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अनेक उपाय करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन उपायों में सम्मिलित हैं:	प्रायोगिक संचालन के लिए समान केवाईसी टेपप्लेट को अंतिम रूप देने और सीईआरएसएआई के माध्यम से अंतिम क्रियान्वयन की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक में चल रही है।
		i) संपूर्ण वित्तीय सेक्टर में, एक समान केवाईसी मानकों को लागू करना केवाईसी रिकार्डों का अन्तर-उपयोग आरंभ करना।	एफएसडीसी उप समिति ने 9.8.2014 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि यह परियोजना केवल वित्तीय आस्तियों की समीक्षा तक समिति रहेगी। तथापि, हिसाब एकीकरण की प्रौद्योगिकी इस प्रकार सीमित होगी कि इसे बाद में संव्यवहारों की सहूलियत के लिए बढ़ाया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में सेबी जैसे अन्य विनियामकों द्वारा किए गए प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक भी सहमत है कि आईआरटीजी हिसाब एकीकरण के लिए इस पद्धति को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त रूपरेखा की स्थापना करने का प्रस्ताव लाए।
		ii) एक ही प्रचालनात्मक डिमैट खाता शुरू करना ताकि भारतीय वित्तीय सेक्टर के उपभोक्ता इसी एक खाते के जरिए सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच सकें और लेन-देन कर सकें।	
		[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	BÉÉÉªÉ |ÉMÉÉiÉ {É®
112	127	वस्तु बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने के भाग के रूप में, भण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण ने भण्डागार सेक्टर को शक्तिशाली बनाने और सौदे-बाजी योग्य भण्डागार	वेयरहाऊसिंग सेक्टर संबंधी बाजार प्रथाओं एवं मुद्दों का अध्ययन करने के लिए, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने वेयरहाऊस सेवा प्रदाताओं, संपार्श्विक प्रबंधकों, बैंकों, अधिवक्ताओं और जिंस एक्सचेंजों के साथ बातचीत की है ताकि ऐसे नियम एवं विनियम

क्रम सं.	उत्तर सं.	प्रश्न	उत्तर
		प्राप्तियों के विरुद्ध किसानों को फसल कटाई पश्चात् ऋण देने में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए परिवर्तन आयोजना शुरू की है। इस आयोजना को उत्साहपूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]	बनाए जा सके जो वेयरहाऊसिंग बाजार की चिंताओं का समाधान करते हों। मात्रात्मक सेंपल के लिए टेंडर प्रलेखों को अंतिम रूप दिया गया है तथा देश में वेयरहाउस सेक्टर का मात्रात्मक सेंपल सर्वे संचालित करने के लिए एक एजेंसी के चयन के लिए टेंडर को अंतिम रूप दिया गया है। वेयरहाउसिंग के क्वालिटी संबंधी सर्वे संचालित करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, बिना किसी वित्तीय विविक्षा के, वेयरहाउस विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए यह सर्वे करेगा। एक प्रोजेक्ट परामर्शदाता रखने के लिए टेंडर दस्तावेजों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्री
113	128	मौजूदा भारतीय लेखाकरण मानकों को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है। मैं, भारतीय कम्पनियों से वित्त वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्त वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से नए भारतीय लेखाकरण मानक अपनाने का प्रस्ताव करता हूँ। विनियामक, अन्तरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर, बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के लिए भारतीय लेखाकरण मानकों के क्रियान्वयन की तारीख अलग से अधिसूचित करेंगे। कर गणना के मानकों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कारपोरेट कार्य मंत्रालय; राजस्व विभाग]	सभी 39 भारतीय लेखा मानकों को एनएसीएएस से परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया है। इन मानकों के क्रियान्वयन की रूपरेखा 02.01.2015 को घोषित की गई है। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 और सभी भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। आय संगणन और प्रकटीकरण मानकों की अधिसूचना के लिए, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145 संशोधित की गई। ये मानक वित्त वर्ष 2015-16 और बाद के वर्षों के लिए आय संगणित करने के लिए लागू होंगे। आय संगणन और प्रकटीकरण मानकों का प्रारूप 30 दिनों की अवधि के लिए जन अभिमत प्राप्त करने हेतु 08.01.2015 को सार्वजनिक कर दिया गया है। इन मानकों को 15 मार्च, 2015 तक अधिसूचित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री
114	129	सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकार, सैद्धांतिक रूप से, इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत है। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]	व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एसबीआई उच्च सीमाओं के लिए कहा गया है। मामला विचाराधीन है। वित्त मंत्री
115	130	देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए, वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम इस वर्ष 15 अगस्त को प्रारंभ किया जाएगा। इसमें समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा, इनमें महिलाएं छोटे और सीमान्त किसान और श्रमिक	''प्रधान मंत्री जन धन योजना'' माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 28.8.2014 को आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत, 28.01.2015 तक 12.31 करोड़ खाते खोले गए हैं। इनमें से, 4.94 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 7.37 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। 8.30 करोड़ खाते शून्य राशि वाले हैं और शेष 4.01 करोड़ खातों में 10217.43 करोड़ रुपए जमा राशि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक खाते के हिसाब से

क्रॅ.सं.	{É®É o.Ç.	¤ÉVÉ] PÉÉKÉhÉÉ	BÉÉÉªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉÉÉ |ÉÉÉº|ÉÉiÉ
		शामिल होंगे। प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो ऋण के लिए भी पात्र होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]	औसत शेष 830.00 रुपए है। 99.98 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। सर्वे परिणाम के अनुसार, 2105.93 लाख परिवारों में से, 2105.52 लाख परिवार शामिल किए गए हैं। BÉÉÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
116	131	इस सेक्टर में, निजी सेक्टर की अपेक्षाकृत बड़ी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में, अवसंरचना हेतु दीर्घावधिक वित्तपोषण बड़ी अड़चन रहा है। आस्ति पक्ष में, बैंकों को अवसंरचना सेक्टर के लिए दीर्घावधिक ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसकी संरचना में लचीलापन होगा, जिससे संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं को आत्मसात किया जा सके, कभी-कभी 5/25 संरचना के रूप में जाना जाता है। देनदारी पक्ष में, बैंकों को अवसंरचना सेक्टर को उधार देने हेतु दीर्घावधिक निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी पूर्व शर्तें कम से कम होंगी जैसे सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिक सेक्टर ऋण (पीएसएल)। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]	भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए 15 जुलाई, 2014 को दो परिपत्र जारी किए हैं जिनमें उन्हें अवसंरचना बंध-पत्रों के माध्यम से दीर्घकालिक निधियां जुटाने और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋणों की संरचना बनाने में नम्यता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। BÉÉÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
117	132	मौजूदा ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद, वर्तमान वित्त वर्ष में निजी सेक्टर में सार्वभौमिक बैंकों के सतत् प्राधिकार के लिए एक ढांचा क्रियान्वित किया जाएगा। छोटे बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों के लाइसेंस देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक एक ढांचा तैयार करेगा। आला हितों की पूर्ति करने वाले विशिष्ट बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक आदि की परिकल्पना छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र, निम्न आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्य बल की ऋण और प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]	निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देने के बारे में अंतिम दिशा-निर्देश, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 नवम्बर, 2014 को अपनी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। ऐसे बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन 16 जनवरी, 2015 तक आमंत्रित किए गए। BÉÉÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
118	133	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां बढ़ना, सरकार के लिए चिंता का विषय है। चंडीगढ़, बेंगलुरू, इरनाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए जाएंगे। अन्य प्रतिबलित आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार कारगर उपाय करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]	मंत्रिमंडल ने 10.12.2014 को मंत्रिमंडल टिप्पण अनुमोदित किया। परिसरों की अवस्थिति, कार्यक्षेत्र नियत करने और पद सृजन के लिए कार्रवाई की जा रही है। BÉÉÉ®´ÉÉ< |ÉMÉÉiÉ {É®

क्रम सं.	उत्तर सं.	तारांकित प्रश्न	अतारांकित प्रश्न

119 134 श्री भर्तृहरि मेहताब

भारत में बीमा के फायदे अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं और बीमा पैठ तथा सघनता बहुत कम है। सरकार बहु-आयामी तरीके से इस स्थिति का समाधान करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए सभी संबंधित हितधारकों की सहायता ली जाएगी। इसमें उपयुक्त प्रोत्साहन, बैंकिंग सम्पर्कियों का उपयोग, सरकारी सेक्टर के बीमा द्वारा खोले गए अतिलघु कार्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल हैं। संसद के विचारार्थ लंबित बीमा विधि (संशोधन) विधेयक को भी लिए जाने का प्रस्ताव है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]

इस उद्घोषणा को पूरा करने के लिए इरडा, एलआईसी और जिप्सा द्वारा कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया गया है तथा उनके कार्य-निष्पादन की मानीटरी के लिए एलआईसी और जिप्सा को मेट्रिक्स भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना में बीमा कंपनियों को विशेष रूप से लाने के लिए, एलआईसी, पीएसजीआईसी, ए आईसीआईएल एवं एसएलबीसी समन्वयकों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के कार्य-निष्पादन की मासिक समीक्षा की जा रही है।

श्री जयन्त सिन्हा

120 135 वित्तीय सेक्टर सुधारों के अंतर्गत कानूनी प्रयासों के भाग के रूप में, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत विनियामक कमी को पाटने का प्रस्ताव है। इस उपाय से, ऐसी कंपनियों और निकायों का कारगर विनियमन हो सकेगा, जिन्होंने देश में बहुत बड़ी संख्या में गरीब एवं कमजोर लोगों को धोखा दिया है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग]

मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी और विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालयों/विभागों से उत्तर मिल गए हैं। मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी और विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री अरुण जेटली

121 136 अल्प बचतबचत दर में गिरावट की और अल्प बचतकर्ताओं के लिए प्रतिलाभ बढ़ाने की चिंताओं के समाधान के लिए, मैं अल्प बचतों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

अल्प बचतों का पुनरुद्धार करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

श्री जयन्त सिन्हा

122 137 मेरी सरकार बालिका कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। कन्या को शिक्षा देने ओर उसके विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक विशेष अल्प बचत लिखत शुरू की जाएगी। अल्प बचतकर्ता को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के लिए, बीमा कवर के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र भी शुरू किया जाएगा।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

योजना 02 दिसम्बर, 2014 को अधिसूचित की गयी।

सुकन्या समृद्धि योजना 22.01.2015 को शुरू की गयी।

श्री जयन्त सिन्हा

123 138 लोक भविष्य निधि स्कीम में, वार्षिक अधिकतम सीमा, मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की जाएगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]

पीपीएफ योजना की उच्च सीमा सालाना 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गयी है।

श्री जयन्त सिन्हा

क्रम संख्या	तारांकित संख्या	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर
124	139	**VII** श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	रक्षा मंत्रालय की मांगों में पहले ही व्यवस्था कर दी गयी है।
		हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अतः, मैं, रक्षा के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 2,29,000 करोड़ रुपए आंवटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।	श्री मनोहर पर्रीकर
		[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय]	
125	140	श्री अजय टम्टा	इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए, रक्षा लेखा महानियंत्रक की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात इस कार्यदल ने एक रैंक एक पेंशन के क्रियान्वयन के लिए कुछ संभावित विकल्प सुझाए। एक रैंक एक पेंशन के क्रियान्वयन के बारे में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा सचिव, सचिव(ईएसडब्ल्यू), वित्त सलाहकार (डीएस) और रक्षा लेखा महानियंत्रक के साथ 26.08.2014 को बैठक की गयी है। तौर-तरीकों पर विचार किया जा रहा है।
		हम अपने साहसी सिपाहियों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि करते हैं। पेंशन विसंगतियां दूर करने के लिए, सरकार द्वारा ''एक रैंक एक पेंशन'' की नीति स्वीकार की गई है। मैं, इस वर्ष की आवश्यकता पूरी करने के लिए, और 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।	श्री मनोहर पर्रीकर
		[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय]	
126	141	श्री राजीव प्रताप रूडी	रक्षा मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध करने का निर्णय किया गया है कि आर्मी ग्रांट के पूंजी भाग में रक्षा रेल नेटवर्क के लिए प्रदान की गयी 1,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन प्रत्यावर्तित किया जाए तथा स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के विकास के लिए उसे रेल बोर्ड को समर्पित अव्यपगत निधियों के रूप में उपलब्ध कराया जाए।
		सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है ताकि भारत के सामरिक हितों की रक्षा करने में वे अपनी कारगर भूमिका निभा सके। अतः, मैं रक्षा हेतु अंतरिम बजट में उपलब्ध करायी पूंजी परिव्यय और 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें, सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल प्रणाली का विकास त्वरित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे ताकि उसे त्वरित और ज्यादा कारगर बनाया जा सके।	श्री मनोहर पर्रीकर
		[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय; रेल मंत्रालय]	
127	142	श्री राजीव प्रताप रूडी	राष्ट्रीय युद्ध स्मारक(म्यूजियम) के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखी जाने वाली टिप्पणी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
		देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए महान बलिदान देने हेतु सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति देश ऋणी है। ऐसा करने में उनमें से बहुतों ने अपनी जान गवांई है। उनके स्मरण में उपयुक्त स्मारक का निर्माण करना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रिन्सेज पार्क में एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसका अनुपूरण युद्ध संग्रहालय द्वारा होगा। इसके लिए, मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन देता हूँ।	श्री मनोहर पर्रीकर
		[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय]	

क्रम.सं.	{É®É o.É.	¤ÉVÉ] PÉÉKÉhÉÉ	BÉEÉ aÉÉx´É aÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÉo lÉÉiÉ

128 143 ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ

वर्ष 2011 में, सरकारी और निजी सेक्टर की कंपनियों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के लिए अलग से एक निधि की घोषणा की गई थी, इसमें एसएमई तथा देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने वाली रक्षा प्रणाली के अनुसंधान और विकास में सहायक शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल हैं। तथापि, घोषणा के अलावा, कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए, इस उद्देश्य की सहायता के लिए, प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने हेतु, मैं 100 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः रक्षा मंत्रालय]

स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत पूरी हो गयी है और मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाने वाली टिप्पणी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

BÉEÉaÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

129 144 +ÉÉiÉÉ®BÉE oÉ®FÉÉ

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम की समीक्षा की जाएगी। मैं, मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटन 2013-14 के 1,847 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में छोटे परन्तु अति आवश्यक विकास कार्य पूरा करने के लिए भी, मैं अतिरिक्त निधियां आवंटित करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]

एमपीएफ योजना को अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए, अपर महानिदेशक, बीपीआरएंडडी की अध्यक्षता में एक समिति 8 सितम्बर, 2014 को गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 03.12.2014 को प्रस्तुत कर दी है।

2014-15 में संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए, 1847 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने के संबंध में मामले को वित्त मंत्रालय के साथ लिया गया है।

BÉEÉaÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

130 145 सीमा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए, 2,250 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गावों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, 990 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। समुद्री पुलिस थाना, जेटीज के निर्माण, और नावों की खरीद आदि के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि भी रखी गयी है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]

तीन आबंटनों में से, क्रमशः 914.30 करोड़ रुपए, 744.56 करोड़ रुपए और 12.88 करोड़ रुपए की राशि 25 जनवरी, 2015 तक खर्च की गई हैं।

BÉEÉaÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

131 146 ®ÉK]ÉaÉ {ÉÉãÉoÉ oàÉÉ®BÉE

पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति राष्ट्र ऋणी है। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी शामिल हैं जो देश के भीतर लगातार दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया में कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। मैं उपयुक्त राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाने की घोषणा करता हूँ। मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए मैं, 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]

चाणक्य पुरी, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल के, एनबीसीसी के माध्यम से, नवीकरण के लिए 53.94 करोड़ रुपए की लागत से, आईबी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है ताकि विद्यमान संरचनाओं का उपयोग किया जा सके तथा डिजाइन डीयूएसी मानकों के अनुरूप हो।

BÉEÉaÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

क्रम सं.	तारांकित प्रश्न सं.	विषय	उत्तर
132	147	**VIII** भारत की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए बड़ी संभावना प्रदान करती है। मैं, विशिष्ट थीमों के इर्द-गिर्द 5 पर्यटक सर्किट बनाने तथा इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यटन मंत्रालय]	एसएफसी ने 18 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में इस योजना का मूल्यांकन किया था। मार्गनिर्देश अनुमोदित किए गए। राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक 14.01.2015 को हुई। योजना को कार्यान्वित करने के लिए मिशन निदेशालय स्थापित किया गया है। श्रीमती रेणु शर्मा
133	148	इस वित्त वर्ष राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरूद्धार और आध्यात्मिक परिवर्धन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए जा रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यटन मंत्रालय]	मार्गनिर्देश अनुमोदित किए गए। राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक 14.01.2015 को हुई। योजना को कार्यान्वित करने के लिए मिशन निदेशालय स्थापित किया गया है। श्रीमती रेणु शर्मा
134	149	विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना लागू की जाएगी। मैं, यह कार्यक्रम मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, बेल्लांकनी और अजमेर जैसे नगरों में आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रयोजन के लिए, मैं 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूँ। किफायती तकनीकों और सहभागिता के आधार पर यह परियोजना सरकार, शैक्षिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः शहरी विकास मंत्रालय]	राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्धन योजना अनुमोदित की गई। यह योजना 21.1.2015 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 12 नगरों अर्थात वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, मथुरा, गया, कांचीपुरम, वेलांकनी, बाड़ामी, अमरावती, वारंगल, पुरी और द्वारका को अभिज्ञात किया गया है। श्रीमती रेणु शर्मा
135	150	पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण की ओर भी अविलम्ब ध्यान दिया जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम कहीं इन प्राचीन विरासतों से हाथ न धो बैठें। इस प्रयोजन के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करना चाहता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]	बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। कार्रवाई शुरू करने के लिए स्मारकों की पहचान की गई है। श्रीमती रेणु शर्मा
136	151	पूरे विश्व से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं से, सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय]	नई स्कीम के मार्ग-निर्देशों को अनुमोदित करके जारी किया गया है। बौद्ध सर्किट सहित पांच सर्किटों को अनुमोदित किया गया है। श्रीमती रेणु शर्मा

क्रम सं.	उत्तर सं.	प्रश्न का विषय	उत्तर
137	152	गोवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। यह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के एक स्थायी स्थल के रूप में भी घोषित हो चुका है। यहां एक विश्वस्तरीय समारोह स्थल विकसित किए जाने की महती आवश्यकता है। यह कार्य निजी क्षेत्र के घनिष्ठ सहयोग से सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है। भारत सरकार वीजीएफ स्कीम के जरिए सरकारी-निजी-सहभागिता के आधार पर सुविधाएं विकसित करने के इस कार्यक्रम को पूरी सहायता देगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः सूचना और प्रसारण मंत्रालय]	गोवा को स्थायी स्थल घोषित करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर गोवा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय मंत्री (सूचना और प्रसारण)
138	153	नदियां हमारे देश की जीवन रेखाएं हैं। ये हमें न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध करती हैं, अपितु पेयजल भी उपलब्ध कराती हैं। दुर्भाग्यवश, इनमें बारह मास समान रूप से पानी नहीं होता। इसलिए नदियों को जोड़ना देश के लिए असाधारण रूप से लाभकारी हो सकता है। यही समय है जब हमने इस दिशा में गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ने का गंभीर प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]	इस कार्यक्रम पर आगे कार्रवाई करने के लिए एक विशेष समिति तारीख 23.09.2014 की अधिसूचना द्वारा गठित की गई है। 16 संभाव्यता रिपोर्टें पूर्ण हो गई हैं, जिनमें से 14 प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत और 2 हिमालयी घटक के अंतर्गत आती हैं। आज की तारीख तक, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भी पूरी हो गई हैं। आयोजना स्कीम के आईडब्ल्यूआरएसडी घटक अर्थात नदी थाला प्रबंधन के अंतर्गत नदी को आपस में जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष 2014-15 में 60 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। नदी को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नियत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में गठित विशेष समिति ने उप-समितियां बनाई हैं। अभी तक नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा तैयार की जा रही हैं। राज्यों को निधियां जारी करने के लिए, एसएफसी की बैठक की जा रही है जिससे राज्य अंतर-राज्यिक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें स्वयं बना सके। केन्द्रीय मंत्री (सूचना और प्रसारण)
139	154	गंगा, इस देश की सामूहिक चेतना में विशिष्ट पावन स्थान रखती है। इस नदी के अनुरक्षण और सुधार के लिए काफी राशि खर्च की जा चुकी है। तथापि, सभी हिताधिकारियों द्वारा किए जाने वाले समन्वित प्रयासों की कमी के चलते, अब तक किए गए प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। मैं, ''नमामि गंगे'' नामक एकीकृत गंगा अनुरक्षण मिशन की स्थापना	इस उद्देश्य के लिए, 2037 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। व्यय वित्त समिति ने 30 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री (सूचना और प्रसारण)

क्रम संख्या	तारांकित संख्या	प्रश्न	उत्तर

का प्रस्ताव करता हूँ और इस प्रयोजन के लिए 2,037 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]

140 155 प्रश्न के उत्तर में दिए गए वक्तव्य का संक्षिप्त रूप

हमारी नदियों के नदी तट और घाट न केवल प्रचुर ऐतिहासिक विरासतयुक्त हैं, अपितु उनमें से अधिकांश पावन स्थल भी हैं। देश में इस प्रक्रिया के श्री गणेश के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में घाट विकास और केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में नदी-तट के सौन्दर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]

व्यय वित्त समिति ने 30 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रगति की समीक्षा की जाएगी

141 156 +ऐसे संस्थानों की स्थापना

भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण जैसे क्षेत्रों के विकास में अनिवासी भारतीयों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में, गंगा नदी के अनुरक्षण को लेकर अनिवासी भारतीयों की प्रेरणा और उत्साह को उपयोग में लाने के लिए, एक अनिवासी भारतीय निधि गठित की जाएगी। यह विशेष परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी।

[नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]

मंत्रिमंडल ने यह योजना 24 सितम्बर, 2014 को अनुमोदित की।

कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है

142 157 उत्कृष्टता केन्द्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ऐसे कई अग्रणी अनुसंधान केंद्र हैं जो नैनोटेक्नोलॉजी, सामग्री विज्ञान, तथा बायोचिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। सरकार इस तरह की कम से कम पांच संस्थाओं को प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र के रूप में सुदृढ़ करेगी ताकि इन्हें सरकारी-निजी-सहभागिता द्वारा नवोन्मेषी अनुसंधान में और प्रभावी बनाया जा सके।

[नोडल मंत्रालय/विभागः विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय]

विशेषज्ञ समितियों/कार्यबलों/परियोजना मूल्यांकन समितियों(पीएसी) द्वारा पांच तकनीकी अनुसंधान केन्द्रों के प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। यह कवायद पांच प्रस्तावों में से तीन के बारे में पूरी कर ली गई है। शेष दो प्रस्तावों के बारे में कवायद चल रही है।

प्रगति की समीक्षा की जाएगी

क्रम.सं.	तारांकित प्रश्न सं.	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर की संक्षिप्त जानकारी
143	158	फरीदाबाद और बेंगलुरू में बायोटेक क्लस्टरों का विकास उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता से और अधिक किया जाएगा। यह प्रयास डिजीज़ बायोलाजी, स्टेम सेल बायोलाजी और हाइ-एंड इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी के लिए मॉडल आरगेनिज्म संसाधनों के आकलन में वैश्विक भागीदारी को जोड़ेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय]	बायोसाइंस क्लस्टर (बी-लाइफ) के लिए, आवश्यक निधियां जनवरी, 2015 के पहले सप्ताह में जारी कर दी गई हैं। फरीदाबाद स्थित एनसीआर बायोटेक सांइस क्लस्टर के लिए, वित्तीय अनुमोदन अंतिम चरण में हैं। डॉ. महेश शर्मा
144	159	मोहाली में अभिनव कृषि बायोटेक क्लस्टरों से प्लांट जेनेटिक तथा फेनो-टाइप प्लेटफार्म का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, निजी तथा सरकारी भागीदारी के आधार पर मोहाली में कृषि पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, पुणे और कोलकाता में भी दो नए क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः बायोटेकनोलोजी विभाग]	मोहाली में स्थित एग्री-बायोटेक क्लस्टर को बढ़ाने, तथा पुणे और कोलकाता में दो नए क्लस्टरों की स्थापना के प्रस्ताव वित्तीय अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं। डॉ. महेश शर्मा
145	160	अंतरराष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो-टेक्नोलाजी केंद्र के दिल्ली घटक को लाइफसाइन्स और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में विश्व अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए भारत के नेतृत्व में वैश्विक भागीदारी विकसित की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः बायोटेकनोलोजी विभाग]	अंतरराष्ट्रीय जैनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी केन्द्र के बारे में मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पण प्रस्तुत कर दिया गया है। इस केन्द्र के कार्यकलापों को जारी रखने के लिए आवश्यक निधियां जारी कर दी गयी हैं। डॉ. महेश शर्मा
146	161	2014-15 में कई प्रमुख अन्तरिक्ष मिशनों की योजना है, जिनमें भारत के भावी हैवी क्षमता वाले लान्चर जीएस.एल.वी. एम.के.-II की प्रायोगिक उड़ान, पी.एस.एल.वी. का वाणिज्यिक प्रक्षेपण और दो और नेवीगेशनल उपग्रह आदि शामिल हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः अंतरिक्ष विभाग]	दो सॉलिड बूस्टर(एस 200) प्राप्त हो गए हैं और उन्हें सॉलिड स्टेज एसेम्बली बिल्डिंग पर मोबाइल लांच पेडस्टल पर असेंबल किया गया। कोर लिक्विड स्टेज (एल-110) पर अबोनिक्स असेम्बलीयुक्त इलैक्ट्रिकल जांच और कार्यात्मक परीक्षण पूरे हो गए हैं। तकनीकी परिसर पर पैसिव क्रायोजेनिक स्टेज (सी 25) कार्यात्मक जांच कर रही है। पीसीएलवी-सी 23 ने कनाडा से फ्रेंच अर्थ ऑबजर्वेशन उपग्रह एसपीओटी-7 और 4 को-पैसेंजर उपग्रह अर्थात. एनएलएस 7.1 और एनएसएस 7.2, एआईएसएटी जर्मनी से और वीएलओएक्स। सिंगापुर से 30 जून, 2014 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए। डॉ. जितेन्द्र सिंह

क्रम संख्या	तारांकित संख्या	प्रश्न	उत्तर
147	162	मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला हमारा अन्तरिक्ष यान डेजिग्नेटेड हेलियो सेन्ट्रिक ट्रैजेक्टरी के साथ अपनी 300 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पर है। मार्स आरबिटर अन्तरिक्ष यान के 24 सितम्बर, 2014 तक मंगलग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। [नोडल मंत्रालय/विभागः अंतरिक्ष विभाग]	
148	163	JÉãÉ iÉlÉÉ aÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉ JÉãÉ खेल प्रगति और वैयक्तिक विकास का एक अभिन्न हिस्सा हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में खेल अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रमुख खेलों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करेगी। निशानेबाजी, तीरन्दाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा विविध ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं के क्षेत्र में, देश में प्रतिभासंपन्न एथलीटों के प्रशिक्षण और जूनियर एवं सब-जूनियर स्तर पर प्रतिभासंपन्न खिलाडियों को आगे बढाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सहूलियतों और सुविधाओं से लैस अकादमियों की स्थापना की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	कनिष्ठ खेल अकादमियों और राष्ट्र स्तरीय खेल अकादमियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है। व्यय वित्त समिति के नोट के शीघ्र ही तैयार होने की संभावना है। BÉEÉaÉ lÉMÉÉiÉ {É®
149	164	जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त खेल प्रतिभाएं विद्यमान हैं किन्तु अपर्याप्त खेल सुविधाओं के कारण वहां के युवक अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। मैं, जम्मू में और कश्मीर घाटी में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले इन्डोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके अनुमोदन के पश्चात, जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार से परामर्श करके पीएमसी कार्यों के लिए पब्लिक सेक्टर उपक्रम का चयन करने हेतु एनआईटी जारी किया जाएगा। BÉEÉaÉ lÉMÉÉiÉ {É®
150	165	मैं, मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। इसके लिए, मैं, चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए जगह का पता मणिपुर के थाउबल उप संभाग के 44-येथीबी में लगाया गया है। फेकल्टी रखने के साथ आवश्यक आधारभूत ढांचा सृजित किए जाने के बाद, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूरी तरह से काम करने लगेगा। निवेश-पूर्व कार्यों के लिए, व्यय विभाग 50 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर सहमत हो गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए, एक पृथक एजेंसी अर्थात हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। BÉEÉaÉ lÉMÉÉiÉ {É®

क्रम संख्या	तारांकित प्रश्न संख्या	माननीय सदस्य का नाम तथा प्रश्न का विषय	उत्तर
151	166	देश के हिमालयी क्षेत्र में तथा इसके विविध भागों में बसे राज्यों में खेलों की अपनी अनोखी परम्पराएं विकसित हुई हैं। इनके विकास के लिए, भारत इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए, वार्षिक खेल आयोजित करेगा और इन खेलों में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे भारतीय राज्यों के साथ-साथ, नेपाल और भूटान जैसे देशों को आमंत्रित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	अवधारणा नोट अनुमोदित किया जा चुका है। एसएफसी ने प्रस्ताव का मूल्यांकन कर लिया है। प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए मसौदा स्कीम तैयार कर ली गई है। समारोह आयोजित करने के तौर-तरीकों पर सचिव(खेल), असम और मणिपुर सरकारों के साथ 19 जनवरी, 2015 को विचार-विमर्श कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि वार्षिक रूप से प्रतियोगिताएं गुवाहाटी, असम में अक्टूबर माह में किसी समय आयोजित की जा सकेंगी। इस प्रयोजनार्थ, 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। स्कीम दस्तावेज अनुमोदित किया जा चुका है। खेल मंत्रालय
152	167	आगामी एशियायी खेलों में भारत के पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। खेल मंत्रालय
153	168	श्री नौकरी की उपलब्धता सम्बन्धी सूचना देने के साथ-साथ रोजगार कार्यालयों को कैरियर केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। ये केंद्र अब युवाओं को परामर्श-सलाह की सुविधा देंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता और रुझान के अनुरूप अपने लिए रोजगार चुन सकें। मैंने इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि नियत की है। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम और रोजगार मंत्रालय]	कैरियर केन्द्रों के लिए एसएफसी, राष्ट्रीय कैरियर सर्विस परियोजना के विशिष्ट घटक के रूप में अनुमोदित की गयी है। मॉडल कैरियर केन्द्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं। प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। खेल मंत्रालय
154	169	भारत का युवा व्यावहारिक, दूरदृष्टि सम्पन्न है और सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनने की इच्छा रखता है। नेतृत्व कौशलों के विकास के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक आवंटन से ''युवा अग्रणी कार्यक्रम'' की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः युवा कार्य और खेल मंत्रालय]	केन्द्रीय सेक्टर की एक नई योजना अर्थात 'राष्ट्रीय यूथ लीडर्स प्रोग्राम' दिसम्बर, 2014 में शुरू की गयी है। खेल मंत्रालय
155	170	**IX** जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इस देश में विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु हमारे विशेष सहयोग की जरूरत है। मैं, चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/ विभागः गृह मंत्रालय]	(क) 500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। (ख) प्रधानमंत्री के विद्यमान पैकेज 2008 में संशोधन के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार से 5820 करोड़ रुपए की वित्तीय विविक्षा वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें, मौजूदा पैकेज के अधिकांश मदों में अभिवृद्धित संशोधन की बात कही गयी है।

क्रम संख्या	तारांकित प्रश्न संख्या	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर की संक्षिप्त रूपरेखा
			(ग) पिछले अनुभव को देखते हुए, यह महसूस किया गया है कि कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास के लिए नए पैकेज को, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके, ध्यानपूर्वक अंतिम रूप दिया जाए। राज्य सरकार के अधिकारियों और प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श हो गए हैं। अब, योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तदनुसार, 2014-15 के बजट में निर्दिष्ट की गयी धनराशि का उपयोग किया जाएगा। (घ) गृह मंत्रालय ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए नकद सहायता वर्तमान 1650 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह करने के लिए अनुमादेन प्रदान कर दिया है।
156	171		एसएफसी मीटिंग की तारीख निश्चित की जा रही है।
		देश में हिमालय अध्ययन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की महती आवश्यकता है। मैं, 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक परिव्यय से उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय]	
157	172		आंध्र प्रदेश सरकार ने अनंतपुर जिले के पलसमुद्रम गांव में अकादमी की स्थापना के लिए 500 एकड़ भूमि आबंटित की है और कार्रवाई की जा रही है।
		हिन्दुपुर, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	
158	173		उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आर्गेनिक खाद्य को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के बजट में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग को 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अवधारणा टिप्पण सहित व्यय वित्त समिति/एसएफसी के समक्ष रखे जाने वाले ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
		भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्गेनिक खेती के विकास की असाधारण क्षमता है। आर्गेनिक खाद्य की पूरी दुनियां में बढ़ रही मांग से, पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले लोग वाणिज्यिक आर्गेनिक खेती के विकास से काफी लाभ कमा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय]	

क्रम सं.	उत्तर सं.	तारांकित प्रश्न	उत्तर
159	174	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल परियोजनाएं समुचित जुड़ाव के अभाव में पूर्वोत्तर क्षेत्र अलगाव की भावना और अपर्याप्त विकास से जूझता रहा है। इस अंतराल को पाटने के लिए यहां रेल प्रणाली का विकास एक तात्कालिक आवश्यकता है। मेरा इरादा इस क्षेत्र में रेल सम्पर्क बढ़ाने का है। इसके लिए, मैं अंतरिम बजट में उपलब्ध करायी गयी राशि के अलावा, 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः रेल मंत्रालय]	पूर्वोत्तर क्षेत्र में 19 रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 9 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। उच्चतर एवं आश्वस्त आबंटन से इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र में कार्यों की सघन मॉनीटरिंग करके, दो नई लाइन परियोजनाएं अर्थात हारमुती से नाहरलगन (ईटानगर) और (ii) दुधनोई-मेंदीपाथर (2014-15 में मेघालय में पहली बार ब्रोडगेज रेल लिंक) पूरी हो गई हैं। एक गेज परिवर्तन परियोजना अर्थात रंगिया-मुकोंगसेलेक (510 कि.मी.) भी पूरी हो गई है और पूरा खंड चालू वित्त वर्ष में काम करने लगेगा। बराक घाटी को जोड़ने अर्थात असम के दक्षिणी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी के लिए ब्रोडगेज रेल लिंक के साथ जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी गेज परिवर्तन परियोजना का लम्डिंग-बदरपुर सिल्चर भाग का अत्यधिक महत्व है। श्री सुरेश प्रभु
160	175	दूरदर्शन पर 24x7 समाचार चैनल सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए और देश की विविधता के प्रति महत्तर जागरूकता सृजित करने हेतु, टी.वी. एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी पहचान को एक सशक्त माध्यम मुहैया कराने की दृष्टि से 24x7 एक चैनल ''अरुण प्रभा'' शुरू किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः सूचना और प्रसारण मंत्रालय]	एसएफसी प्रस्ताव 29.08.2014 को प्राप्त हुआ। मंत्रालय की टिप्पणी से प्रसार भारती को 24.09.2014 को अवगत करा दिया गया है। मामला प्रसार भारती में विचाराधीन है। श्री मनीष तिवारी
161	176	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मेरी सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास से सम्बंधित सभी मसलों के त्वरित निवारण के लिए कृत संकल्प है। संघीय सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दोनों ही राज्यों के सम्बन्ध में विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रावधान किए गए हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास के निम्नलिखित कार्य-कलाप किए जा रहे हैं: • वाम अतिवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना स्कीम, विजाग में ग्रेहाउन्डस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना। • विशाखापट्टनम और गुंटुर-विजयवाडा-तेनाली में मेट्रो रेल की संभाव्यता। • एक नए रेलवे जोन की स्थापना, तेलंगाना में रेल कोच फैक्टरी की संभाव्यता। • तेलंगाना में एनटीपीसी द्वारा 4000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना। • अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति का विस्तार करने की संभाव्यता की जांच।

क्रम संख्या	तारांकित संख्या	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर की विषय-वस्तु

ºÉ½BÉÉ {ÉÉ®´ÉcxÉ +ÉÉ® ®ÉVÉàÉÉMÉ àÉjÉÉãÉaÉ: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इसमें 4,207 कि.मी. की लम्बाई सम्मिलित है। नई राजधानी को हैदराबाद से और तेलंगाना के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से सड़क कनेक्टविटी के माध्यम से जोड़ना।

{É]ÉÉãÉaÉàÉ +ÉÉ® |ÉÉBÉÉÉiÉBÉÉ MÉºÉ àÉjÉÉãÉaÉ: पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना, आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की संभाव्यता।

{ÉÉiÉ {ÉÉ®´ÉcxÉ àÉjÉÉãÉaÉ: दुग्गुरागपट्टनम बंदरगाह की स्थापना।

àÉÉxÉ´É ºÉºÉÉvÉxÉ É´ÉBÉÉÉºÉ àÉjÉÉãÉaÉ: आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, जनजातीय विश्वविद्यालय, एनआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना।

BÉÉBÉ +ÉxÉºÉvÉÉxÉ +ÉÉ® É¶ÉFÉÉ É´ÉÉÉÉMÉ: तेलंगाना में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना।

É´ÉtÉiÉ àÉjÉÉãÉaÉ: तेलंगाना में 4000 मेगावाट क्षमता के प्लांट की स्थापना।

+ÉÉtÉÉÉMÉBÉÉ xÉÉÉiÉ +ÉÉ® ºÉ´ÉvÉxÉ É´ÉÉÉÉMÉ: विज़ाग-चेन्नई आद्यौगिक कॉरीडोर की संभाव्यता।

BÉÉÉaÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

162 177 ®ÉK]ÉaÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉ FÉjÉ, ÉnãÉÉ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली हर साल भारी संख्या में बाहर से आने वाले लोगों से जूझती रही है। इससे दिल्ली ट्रांसमिशन सम्बन्धी विविध समस्याओं और जल-वितरण और आपूर्ति की अड़चनों से त्रस्त है। इन सभी समस्याओं से पार पाने और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय नगर के रूप में विकसित करने के लिए, मैं विद्युत सुधारों के लिए 200 करोड़ रुपए तथा जल सुधारों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूँ।

[नोडल मंत्रालय/विभागः दिल्ली सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]

É´ÉtÉiÉ ºÉvÉÉ®: योजना अनुमोदित कर दी गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

VÉãÉ ºÉvÉÉ®: एसएफसी ने 16.12.2014 को हुई अपनी बैठक में रेणुका बांध के लिए 450 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को 270 करोड़ रुपए की राशि 22 दिसम्बर, 2014 को जारी की गई।

BÉÉÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ

163 178 इसके अलावा, राजधानी क्षेत्र के दीर्घावधिक जलापूर्ति मुद्दों के समाधान के लिए, लम्बे अर्से से लम्बित रेणुका बांध का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा। इसके लिए, मैंने 50 करोड़ रुपए की आरम्भिक राशि की व्यवस्था की है।

[नोडल मंत्रालय/विभागः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय]

रेणुका बांध के लिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को 50 करोड़ रुपए की राशि 22 दिसम्बर, 2014 को जारी की गई।

BÉÉÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ

क्रम सं.	उत्तर सं.	माननीय सदस्य का नाम	उत्तर का संक्षिप्त विवरण
164	179	अंडमान और निकोबार दीप समूह और पुडुचेरीअंडमान और निकोबार दीप समूह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का अटूट अंग हैं। इस द्वीप समूह की संचार संबंधी समस्याओं के समाधन के लिए, मैं 150 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]	गृह मंत्रालय ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के बजट के लिए अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की। बीएसएनएल ने प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कियाः • बीएसएनएल इन्सैट-3सी में सी-बैंड ट्रांसपोन्डर्स में आंतरिक समायोजन करके अक्टूबर, 2014 की समाप्ति तक, अतिरिक्त 50 एमबीपीएस द्वारा बैंडविड्थ बढ़ाएगा। • थाइकोम-6 से अतिरिक्त ट्रांसपोन्डरस किराये पर लेकर जनवरी, 2015 की समाप्ति तक और 300 एमबीपीएस द्वारा बैंडविड्थ बढ़ाई जाएगी। थाइकोम-6 के शीघ्र ही लांच होने की उम्मीद है। • इसरो के जीसैट-16 से 6-8 ट्रांसपोन्डरों का उपयोग करके मई, 2015 तक बैंडविड्थ क्षमता और 300 एमबीपीएस तक बढ़ाई जाएगी। मेनलैंड सहित अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और अंतर द्वीप समूह के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अतिरिक्त सैटेलाइट ट्रांसपोन्डर को भाड़े पर लेने हेतु बीएसएनएल को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यय वित्त समिति के लिए ज्ञापन दूर संचार विभाग को 9.10.2014 को इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रस्ताव की जांच कर ली जाए तथा इस प्रस्ताव में अंतर्ग्रस्त वित्तीय विविक्षा के बारे में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। वित्तीय सहमति 19.1.2015 को दी गई। संचार मंत्रालय
165	180	इसी प्रकार, आपदा-रोधी तैयारियों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, मैं पुडुचेरी को 188 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]	188 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। पुडुचेरी सरकार अपने तारीख 04 सितम्बर, 2014 के पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के क्रियान्वयन के कारण 88,98,62,132/- रुपए की राशि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 17.10.2014 को जारी कर दी गई। 99.01 करोड़ रुपए जारी करने के लिए पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। गृह मंत्रालय
166	249	आयात और निर्यात कार्गो की त्वरित निकासी से परिवहन लागत कम हो जाती है और कारबार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद के लिए, विद्यमान 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन सुविधा को, सभी निर्यात-वस्तुओं के संबंध में 13 और हवाई	31.12.2014 से, 18 समुद्री पत्तनों पर विनिर्दिष्ट आयातों अर्थात इसमें प्रविष्टि के ''सुविधा प्राप्त'' बिल में शामिल वस्तुएं और कारखाना माल से भरे कंटेनर और विनिर्दिष्ट निर्यातों तथा निशुल्क लदान पत्रों के अंतर्गत निर्यातित सामान के लिए 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन की सुविधा शुरू की गई है। इसी प्रकार, 31.12.2014

क्रम संख्या	{ÉÞÉ oÉë.	¤ÉVÉ] PÉÉKÉhÉÉ	BÉEÉÉªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÉ |ÉÉÉºIÉÉiÉ
		अड्डों के लिए तथा निर्दिष्ट आयात-निर्यात माल के संबंध में 14 और बंदरगाहों के लिए, देने के उपाय शुरु किए गए हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	से, 17 हवाई कार्गो परिसरों में विशिष्ट आयातों अर्थात प्रविष्टि के सुविधा प्राप्त बिलों में शामिल वस्तुओं और लदान-पत्रों में शामिल सामान के समस्त निर्यातों के लिए 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन की सुविधा शुरू की गई है। BÉEÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
167	250	व्यापार को सुकर बनाने के लिए ''भारतीय कस्टम सिंगल विंडो प्रोजेक्ट'' कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत, आयातक और निर्यातक अपने समाशोधन दस्तावेजों को केवल एकल केंद्र पर दर्ज कराएंगे। यदि किसी अन्य विनियामक एजेंसियों से कोई अनुमति लेनी अपेक्षित हुई तो उसे ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा तथा व्यापारी को इन एजेंसियों से सम्पर्क करने की आश्यकता नहीं होगी। सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क करके, कारबार करने में लगने वाला समय एवं लागत कम हो जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	सीमा-शुल्क समाशोधन में तेजी लाने के लिए सीमा-शुल्क सिंगल विंडो समाशोधन परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा, सीमा-शुल्क भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण/प्लांट क्वारनटाइन के बीच 31.3.2015 तक ऑनलाइन संदेश आदान-प्रदान स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है BÉEÉªÉ |ÉMÉÉiÉ {É®
168	*	फूड पार्क के रूप में निर्दिष्ट की जा रही कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को वहनीय ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड में 2,000 करोड़ रुपए की एक विशिष्ट निधि की स्थापना करना। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय]	भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26.8.2014 को नाबार्ड को 2,000 करोड़ रुपए आबंटित किए। नाबार्ड द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। BÉEÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
169	*	वित्त विधेयक में संशोधन करके पवन ऊर्जा के लिए त्वरित प्रसुविधा को बहाल करना। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	01 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद संस्थापित पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 80 प्रतिशत की दर पर त्वरित ह्रास प्रसुविधा की बहाली के लिए अधिसूचना 16 सितम्बर, 2014 को जारी कर दी गई है। BÉEÉ®´ÉÉ< {ÉhÉ
170	*	पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में 50 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से नशा-मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना। [नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय]	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 07.11. 2014 को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि इस मामले पर पीआईपी-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से, कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम ने कहा है कि इस प्रस्ताव को अपने पीआईपी में मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पंजाब सरकार के माध्यम से अपर सचिव व एमडी (एनएचएम) को अग्रेषित कर दिया जाए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 19 नवम्बर, 2014 को मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पंजाब सरकार को लिखे पत्र को भी देख लिया जाए जिसकी प्रति अन्य के साथ, संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार को पृष्ठांकित की गई है। BÉEÉªÉ |ÉMÉÉiÉ {É®

** ये घोषणाएं 18.07.2014 को संसद में बजट भाषण पर हुई चर्चा के दौरान की गई थी।*